शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 18 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 27 – 04 मई 2026 मूल्य पांच रूपये

76 करोड़ के बजट और जमीनी हकीकत के बीच फंसी तकनीकी शिक्षा

हिमाचल के तकनीकी कॉलेजों में स्टाफ की कमी, खाली लैब और कमजोर प्लेसमेंट पर उठ रहे सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर ने वित्त वर्ष 2026 – 27 के लिए 76.07 करोड़ रुपये का बजट पारित कर तकनीकी शिक्षा, शोध और नवाचार को नई दिशा देने का दावा किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और विश्वविद्यालय प्रशासन इसे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम बता रहे हैं। बजट में शोध, पीएचडी कार्यक्रम, आधुनिक प्रयोगशालाओं, ई – लाइब्रेरी, उद्यमिता विकास और छात्र गतिविधियों के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। लेकिन इन घोषणाओं के बीच बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रदेश के तकनीकी कॉलेजों की जमीनी स्थिति वास्तव में इतनी मजबूत है कि इन योजनाओं का लाभ छात्रों तक पहुंच सके।

प्रदेश में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी और निजी इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, मैनेजमेंट और तकनीकी संस्थान संचालित हो रहे हैं। इनमें सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के अलावा कई निजी तकनीकी संस्थान भी शामिल हैं। वर्षो से इन संस्थानों में फैकल्टी की कमी, कमजोर प्रयोगशालाएं, सीमित प्लेसमेंट, पुराने उपकरण और घटती छात्र संख्या जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय का नया बजट उम्मीद जरूर पैदा करता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि पहले मौजूदा ढांचे की वास्तविक स्थिति को समझा जाए।

हमीरपुर स्थित तकनीकी विश्वविद्यालय प्रदेश का प्रमुख तकनीकी संस्थान है, लेकिन यहां भी कई विभागों में नियमित फैकल्टी की कमी लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। कई विभाग अतिथि शिक्षकों या अनुबंध आधारित स्टाफ के सहारे चल रहे हैं। छात्रों का कहना है कि रिसर्च और इनोवेशन की बातें तो की जाती हैं, लेकिन कई बार प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों की कमी के कारण व्यावहारिक शिक्षा प्रभावित होती है। विश्वविद्यालय ने अब प्रयोगशालाओं और तकनीकी ढांचे के लिए तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे वर्षो से चली आ रही बुनियादी समस्याएं दूर हो पाएंगी।

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हमीरपुर, अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान प्रगति नगर, हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला, बिलासपुर और अन्य सरकारी तकनीकी संस्थानों की स्थिति भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं मानी जाती। कई संस्थानों में स्थायी शिक्षकों के पद खाली हैं। कुछ कॉलेजों में छात्र संख्या लगातार घट रही है, जिसके कारण कई ब्रांचों में सीटें खाली रह जाती हैं। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि जब तक उद्योगों के साथ मजबूत संबंध और बेहतर प्लेसमेंट नहीं होंगे, तब तक तकनीकी शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ाना मुश्किल होगा।

निजी तकनीकी कॉलेजों की स्थिति भी अलग नहीं है। प्रदेश के कई निजी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज पिछले कुछ वर्षो में कम दाखिलों की समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ संस्थानों में पर्याप्त फैकल्टी नहीं है, जबकि कई जगहों पर प्रयोगशालाएं केवल निरीक्षण के समय सक्रिय दिखाई देती हैं। छात्रों का आरोप है कि कई निजी संस्थानों में फीस तो अधिक ली जाती है, लेकिन सुविधाएं अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलतीं। प्लेसमेंट के नाम पर भी सीमित अवसर उपलब्ध होते हैं और अधिकतर छात्रों को प्रदेश से बाहर रोजगार तलाशना पड़ता है।

तकनीकी विश्वविद्यालय ने अब पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने और शोध संस्कृति को मजबूत करने की घोषणा की है। इसके लिए शोध मार्गदर्शकों को प्रोत्साहन राशि देने तथा शोध पत्रिकाओं और ई – पुस्तकों के लिए बजट तय किया गया है। यह कदम सकारात्मक माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि शोध केवल बजट से मजबूत नहीं होता। इसके लिए योग्य फैकल्टी, आधुनिक रिसर्च लैब, उद्योगों से साझेदारी और लंबे समय की अकादमिक योजना जरूरी होती है। यदि कॉलेजों में बुनियादी शिक्षण व्यवस्था ही कमजोर रहेगी, तो शोध और नवाचार के बड़े दावे जमीन पर असर नहीं छोड़ पाएंगे।

विश्वविद्यालय ने खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, सॉफ्ट स्किल और उद्यमिता विकास के लिए भी बजट बढ़ाया है। छात्र गतिविधियों और कौशल विकास के लिए 70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। हालांकि कई कॉलेजों के छात्र बताते हैं कि कैंपस स्तर पर नियमित तकनीकी फेस्ट, इनोवेशन प्रोग्राम और इंडस्ट्री इंटरैक्शन की कमी रहती है। कई कॉलेजों में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं। ऐसे में बजट प्रावधानों के साथ – साथ उनकी प्रभावी निगरानी भी जरूरी होगी।

सबसे बड़ा सवाल रोजगार को लेकर है। प्रदेश के तकनीकी संस्थानों से हर साल बड़ी संख्या में छात्र पास आउट होते हैं, लेकिन उनमें से काफी छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल पाता। आईटी और कोर सेक्टर की बड़ी कंपनियों की सीमित मौजूदगी के कारण छात्रों को चंडीगढ़, दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। कई छात्र डिग्री पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी या दूसरे क्षेत्रों में रोजगार तलाशने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में सरकार के 'रोजगार सृजन' और 'उद्यमिता' के दावों की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कॉलेज स्तर पर कितने प्रभावी अवसर तैयार होते हैं।

तकनीकी शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश में तकनीकी संस्थानों की संख्या बढ़ाने के साथ – साथ उनकी गुणवत्ता पर भी गंभीर ध्यान देने की जरूरत है। कई कॉलेजों में सीटें खाली रहना इस बात का संकेत है कि छात्र अब केवल डिग्री नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर करियर अवसर चाहते हैं। यदि कॉलेजों में आधुनिक तकनीक, उद्योग आधारित पाठयक्रम, प्रशिक्षित फैकल्टी और मजबूत प्लेसमेंट व्यवस्था नहीं होगी तो नए बजट का असर सीमित रह जाएगा।

सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन तकनीकी शिक्षा में सुधार के बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष और छात्र इन घोषणाओं को जमीनी हकीकत से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि पहले कॉलेजों में खाली पद भरे जाएं, पुरानी मशीनें बदली जाएं, इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं मजबूत की जाएं तथा उद्योगों के साथ वास्तविक साझेदारी विकसित की जाए। केवल बजट घोषणाओं और नई योजनाओं से तकनीकी शिक्षा मजबूत नहीं होगी, बल्कि इसके लिए संस्थानों की वास्तविक समस्याओं को स्वीकार कर उनका समाधान करना होगा।

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का भविष्य अब इसी बात पर निर्भर करेगा कि सरकार इन घोषणाओं को कितनी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ लागू करती है। यदि बजट का उपयोग वास्तव में बुनियादी सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और रोजगार आधारित प्रशिक्षण पर होता है, तो यह तकनीकी शिक्षा के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। लेकिन यदि समस्याएं पहले की तरह बनी रहीं, तो करोड़ों रुपये के बजट और बड़े दावों के बावजूद छात्र बेहतर अवसरों के लिए प्रदेश से बाहर जाने को मजबूर रहेंगे।

राज्यपाल ने वर्चुअल माध्यम से चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के 17वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के 17वें दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए युवा वैज्ञानिकों से अनुसंधान को सीधे किसानों के

हित से जोड़ने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीक और शोध तभी सार्थक होंगे, जब उनका लाभ खेतों तक पहुंचे और किसानों की आय में वृद्धि हो।

राज्यपाल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि इससे कृषि उत्पादकता में सुधार होगा और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का अहम आधार है और इसे मजबूत करने में वैज्ञानिकों और शोधार्थियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दीक्षांत समारोह को जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और स्वर्ण पदक विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह केवल शिक्षा पूर्ण करने का अवसर नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का समय भी है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज के व्यापक हित में करें।

उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि इस संस्थान ने अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में कृषि के महत्व का उल्लेख करते हुए बताया कि बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी इस पर निर्भर है और यह राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

उन्होंने अंत में वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे अपने शोध को प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखें, बल्कि उसे किसानों तक पहुंचाकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। इससे कृषि क्षेत्र के साथ-साथ समग्र विकास को भी गति मिलेगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शिमला में गरिमामय विदाई

शिमला/शैल। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हिमाचल प्रदेश के पांच दिवसीय प्रवास के उपरांत शिमला के अनाडेल हेलीपैड पर

गरिमामय विदाई दी गई।

इस अवसर पर राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू विशेष रूप से उपस्थित रहे। विदाई समारोह में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी सहित प्रशासन, पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

राष्ट्रपति ने दिल्ली रवाना होने से पूर्व शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल भी उनके साथ उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति के इस पांच दिवसीय दौरे को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर राज्य के विकास, प्रशासनिक गतिविधियों और सैन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

नौणी विवि में विभिन्न पाठयक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। औद्यानिकी, वानिकी, प्राकृतिक खेती, जैव प्रौद्योगिकी, फूड टेक्नोलॉजी और एग्री-बिजनेस जैसे क्षेत्रों में रुचि रखने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

स्नातक स्तर पर मुख्य परिसर नौणी, नेरी और थुनाग स्थित महाविद्यालयों में बीएससी (ऑनर्स) औद्यानिकी और वानिकी के साथ बीएससी कृषि (ऑनर्स) प्राकृतिक खेती तथा बीटेक फूड टेक्नोलॉजी जैसे पाठयक्रम उपलब्ध हैं। वहीं, नेरी में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी कार्यक्रमों के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।

स्नातकोत्तर स्तर पर एमएससी में औद्यानिकी और वानिकी के अंतर्गत विभिन्न विशेषज्ञताओं के साथ एमबीए एग्री-बिजनेस मैनेजमेंट पाठयक्रम भी उपलब्ध है।

यूजी (सामान्य सीटों) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून और स्व-वित्तपोषित सीटों के लिए 18 जुलाई है, जबकि पीजी कार्यक्रमों के लिए 23 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। प्रवेश परीक्षाएं 21 जून (यूजी) और 5 जुलाई (पीजी) को आयोजित होंगी।

सामान्य सीटें हिमाचल के मूल निवासियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि स्व-वित्तपोषित सीटों पर देशभर के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश मेरिट और प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा।

लोक भवन में गुजरात-महाराष्ट्र स्थापना दिवस: एकता का सशक्त संदेश

शिमला/शैल। लोक भवन में गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना

दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह ने 'विविधता में एकता' की भारतीय भावना को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। इस गरिमामय कार्यक्रम में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहे दोनों राज्यों के लोगों को एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ इस अवसर को मनाने का संदेश दिया।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के आयोजन विभिन्न प्रदेशों के लोगों को एक मंच पर लाकर आपसी समझ और सौहार्द को सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से 'विविधता में एकता' की भावना को और मजबूत बनाने का आहवान किया।

समारोह के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र से जुड़े प्रतिभागियों ने राज्यपाल के साथ संवाद किया और अपनी सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और रीति-रिवाजों की जानकारी साझा की। यह संवाद कार्यक्रम केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विचारों के आदान-प्रदान का एक प्रभावी मंच बनकर उभरा।

राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजन राष्ट्रीय एकता और अपनत्व की भावना को गहराई प्रदान करते हैं। उन्होंने भारत की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक पहचान का उल्लेख करते हुए कहा कि विविधताओं के बावजूद देश एक सूत्र में बंधा हुआ है, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 'वसुधैव कुटुम्बकम' की अवधारणा को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस जैसे आयोजन इस महान विचारधारा को साकार करते हैं।

कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल ने अतिथियों को हिमाचली टोपी और मफलर भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज भी उपस्थित रहे।

शिमला के शनान क्षेत्र में सड़क व एम्बुलेंस सुविधा का अभाव

शिमला/शैल। शिमला के शनान क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर एक स्थानीय नागरिक ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किये हैं। नागरिक का आरोप है कि वर्षों से सड़क और एम्बुलेंस सुविधा न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन संबंधित विभागों की ओर से कोई ठोस कारवाई नहीं की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 28 जनवरी 2026 को प्रशासन को ईमेल के माध्यम से क्षेत्र में जर्जर सार्वजनिक मार्ग और एम्बुलेंस रोड की अनुपलब्धता के बारे में अवगत कराया था, लेकिन अब तक न तो कोई जवाब मिला और न ही समस्या का समाधान किया गया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह स्वयं पैर में फ्रैक्चर के चलते गंभीर स्थिति में हैं और घर तक पहुंचने के लिए सुरक्षित मार्ग न होने के कारण अपने ही शहर में होटल में रहने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2015 से इस समस्या को लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।

उन्होंने इसे केवल असुविधा नहीं, बल्कि बुनियादी जीवन से जुड़ा मुद्दा बताते हुए प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की है। नागरिक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह कोई विलासिता की मांग नहीं, बल्कि आवश्यक सुविधा है, जो हर नागरिक का अधिकार है।

इस मामले में शिकायतकर्ता ने प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेने, संबंधित विभाग की पहचान करने, समयबद्ध कार्ययोजना बनाने और अंतरिम राहत के रूप में सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो इस मुद्दे को उच्च स्तर तक उठाया जाएगा।

हालांकि, इस संबंध में प्रशासन की ओर से खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है।

कुल्लू में दर्दनाक सड़क हादसा, चार की मौत पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने जताया शोक

शिमला/शैल। कुल्लू जिले के आनी क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब सात लोगों को लेकर जा रही एक गाडी पर अचानक पेड़ गिर गया।

घटना के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे के कारण क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इसे अत्यंत हृदयविदारक बताते हुए कहा कि यह पूरे क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और प्रशासन को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में 'जलवायु परिवर्तन जनित आपदाएं एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा किया गया, जिसमें 51 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 7 सत्रों में 14 व्याख्यान आयोजित हुए।

विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, सूखा प्रबंधन, भूस्खलन नियंत्रण, जलस्रोत प्रबंधन और सतत विकास पर जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान से आए विशेषज्ञों ने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

समापन अवसर पर अधिष्ठाता डॉ. सी.एल. ठाकुर ने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लागू करने का आहवान किया।

मुख्यमंत्री ने नगर निगम शिमला के 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय से नगर निगम शिमला

के कचरा संग्रहण हेतु 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के साथ नगर निगम शिमला राज्य का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है, जिसने चरणबद्ध तरीके से अपने कचरा प्रबंधन वाहन बेड़े को इलेक्ट्रिक बेड़े में बदलने की शुरुआत की है।

इन वाहनों के संचालन से पहले 10 से 14 नवंबर 2025 के बीच परीक्षण किए गए, जिनमें शिमला की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में इनका प्रदर्शन सफल रहा। प्रत्येक वाहन की कचरा संग्रहण क्षमता एक टन है और इन्हें लगभग 13.98 लाख रुपये प्रति वाहन की लागत से खरीदा गया है। नगर निगम परिसर में इनके लिए चार्जिंग अवसंरचना भी स्थापित की गई है, जिससे इनका संचालन सुगम और प्रभावी रहेगा। एक बार पूर्ण चार्ज होने पर ये वाहन लगभग 130 से 150 किलोमीटर तक चल सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे वर्तमान सरकार के पहले बजट में ही प्राथमिकता दी गई थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लक्ष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इन वाहनों से नगर निगम के खर्च में भी कमी आएगी।

इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान महापौर सुरेन्द्र चौहान उप-महापौर उमा कौशल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

12वीं के उत्कृष्ट परिणामों पर मुख्यमंत्री की बधाई, विद्यार्थियों के परिश्रम की सराहना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह सफलता उनके निरंतर परिश्रम, अनुशासन और पढ़ाई के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि इस उपलब्धि के पीछे उनके माता-पिता, शिक्षकों और शुभचिंतकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे हमेशा स्मरण रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और इसे केवल कड़ी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के बल पर ही हासिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए आगे बढ़ने और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री से पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट की मुलाकात, मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स

जॉइंट फ्रंट के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम ने किया। इस दौरान पेंशनरों से जुड़ी विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया और एक विस्तृत मांग-पत्र भी सौंपा गया।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बीते साढ़े तीन वर्षों में वित्तीय चुनौतियों और आरडीजी बंद होने के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने के लिए 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता रोके जाने का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को संशोधित वेतनमान से संबंधित सभी बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा, 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लंबित मामलों का भी निपटारा कर दिया गया है।

इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान सहित फ्रंट के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

लंबित मामलों के निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पहल

शिमला/शैल। आम लोगों को त्वरित और सरल न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'समाधान समारोह 2026' अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत लंबित मामलों को आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण चम्बा के सचिव एकांश कपिल ने बताया कि इस विशेष अभियान का शुभारंभ 21 अप्रैल 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया गया है।

उन्होंने बताया कि समाधान समारोह के अंतर्गत देशभर में राज्य, जिला, तालुका और उच्च न्यायालय स्तर पर स्थापित मध्यस्थता केंद्रों में लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों के बीच बातचीत करवाकर सहमति बनाने में मदद कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों का जल्द और शांतिपूर्ण समाधान करना है। पक्षकार इन बैठकों में व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन माध्यम से भी भाग ले सकते हैं।

सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण चम्बा एकांश कपिल ने बताया कि इस विशेष अभियान का समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित विशेष लोक अदालतों के साथ होगा। इन लोक अदालतों में उन मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें आपसी सहमति से निपटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से समय और धन दोनों की बचत होती है तथा लोगों को जल्दी न्याय मिलता है।

उन्होंने अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षकारों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि लंबित मामलों को समाधान समारोह, विशेष लोक अदालत 2026 में शामिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर एक सरल गूगल फॉर्म उपलब्ध करवाया गया है। इच्छुक पक्षकार 31 मई 2026 तक फॉर्म भरकर अपने मामले को इस विशेष लोक अदालत में शामिल करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए समाधान समारोह के वन स्टॉप सेंटर और संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।

24 रेड जोन पंचायतों में नशे के खिलाफ बनेगी विशेष रणनीति

शिमला/शैल। मंडी जिले में बढ़ते नशे के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। जिला स्तरीय नार्को समन्वय केन्द्र समिति

(एनसीओआरडी) की मासिक बैठक में उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले की 24 रेड जोन पंचायतों में एक सप्ताह के भीतर नशे की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि इस रणनीति में सभी विभागों की जिम्मेदारियां तय होंगी और उसी के अनुसार कारवाई सुनिश्चित की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि केवल ड्रग्स की सप्लाई रोकना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसकी मांग को खत्म करना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए युवाओं में जागरूकता बढ़ाने और समाज को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है।

बैठक में उपायुक्त ने पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और राजस्व विभाग के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जब भी कानून प्रवर्तन एजेंसियां कारवाई के लिए बुलाएं तो संबंधित अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचें और यदि गवाह के रूप में बुलाया जाए तो उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी और एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा।

उपायुक्त ने वन विभाग को विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस समय भांग के पौधे उगने का मौसम है और वन भूमि पर अवैध खेती रोकने के लिए लगातार निगरानी जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि वन भूमि पर यदि भांग या पोस्त की खेती पाई जाती है तो तुरंत कारवाई की जाए और स्वत: उगे पौधों को भी नष्ट किया जाए। प्रशासन का मानना है कि शुरुआती स्तर पर कारवाई से नशे के कारोबार को काफी हद तक रोका जा सकता है।

शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। उपायुक्त ने स्कूलों और कॉलेजों के आसपास स्थित दुकानों की नियमित जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभी तक जिले में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। इसके साथ ही 'अपना विद्यालय' कार्यक्रम के तहत अधिकारियों को स्कूलों का नियमित दौरा करने और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने को कहा गया है।

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत अब तक 122 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 178 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें चरस, हेरोइन, अफीम, प्रतिबंधित दवाओं तथा अवैध खेती से जुड़े मामले शामिल हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु वर्मा ने कहा कि यदि किसी को शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री की सूचना मिलती है तो वह पुलिस अधिकारियों को जानकारी दे सकता है और उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय मॉडल का अध्ययन

शिमला/शैल। जनजातीय विकास विभाग की टीम ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा के नेतृत्व में 25 से 29 अप्रैल, 2026 तक असम और मेघालय का अध्ययन दौरा किया। इस दौरान टीम ने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और विभागों की कार्यप्रणाली को समझा।

टीम ने शिलांग में फेडरिक खारकोंगोर तथा दिसपुर में स्वीटी चांगसन के साथ बैठकों में भाग लेकर विकास मॉडल पर विचार-विमर्श किया।

ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि इस दौरे से पूर्वोत्तर राज्यों के सफल जनजातीय विकास मॉडल और अनुसंधान आधारित नीति निर्माण की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि ऐसी नीतियां जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति दे सकती हैं।

हिमाचल में शहरी निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 17 मई को होगा मतदान

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा अधिसूचित शहरी निकाय चुनावों के तहत नामांकन प्रक्रिया 2 मई 2026 को संपन्न हो गई। आयोग के अनुसार, प्रदेशभर में कुल 1426 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। आयोग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, नामांकन पत्रों की जांच 4 मई 2026 को संबंधित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इसके बाद नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 6 मई 2026 निर्धारित की गई है। मतदान 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा।

जिला कांगड़ा में सबसे अधिक 269 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं, जबकि मंडी में 214 और शिमला में 167 नामांकन प्राप्त हुए। अन्य जिलों में कुल्लू में 125, चंबा में 113, ऊना में 137, सोलन में 158, सिरमौर में 92, हमीरपुर में 55 और बिलासपुर में 96 नामांकन पत्र जमा हुए हैं।

नामांकन के अंतिम दिन 2 मई को अकेले 721 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जबकि 30 अप्रैल को 550 और 29 अप्रैल को 155 नामांकन पत्र जमा हुए थे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के प्रशासन को चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।

शांति का कोई रास्ता नहीं है, केवल शांति है।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

जनादेश की सच्चाई और बदलता राजनीतिक परिदृश्य

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां जनता समय-समय पर सत्ता को आईना दिखाती रहती है। चुनाव परिणाम सिर्फ यह तय नहीं करते कि सरकार किसकी बनेगी, बल्कि यह भी बताते हैं कि जनता क्या सोच रही है, क्या चाहती है और किससे नाराज है। हाल ही में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति को एक स्पष्ट संदेश दिया है।

अगर इन पांचों राज्यों के परिणामों को एक साथ देखें, तो एक बहुत स्पष्ट तस्वीर सामने आती है कि भारत का मतदाता अब किसी भी दल से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। वह हर चुनाव में नए सिरे से फैसला करता है और हर बार अपने हितों को प्राथमिकता देता है। आज की राजनीति में 'वोट फॉर' से ज्यादा 'वोट अगेंस्ट' काम कर रहा है। यानी लोग किसी पार्टी को पसंद करके नहीं, बल्कि दूसरी पार्टी से नाराज होकर वोट दे रहे हैं।

कांग्रेस के संदर्भ में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब उसे 'स्वाभाविक विकल्प' नहीं माना जाता। पहले जहां सत्ता विरोधी माहौल में लोग सीधे कांग्रेस की ओर देखते थे, अब ऐसा नहीं है। आज कांग्रेस केवल एक विकल्प बनकर रह गई है, जिसे जनता परिस्थितियों के अनुसार चुनती है।

वहीं भाजपा के प्रति जनमत दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक वर्ग उसे मजबूत नेतृत्व और निर्णायक सरकार के रूप में देखता है, जबकि दूसरा वर्ग उसे वैचारिक कठोरता और केंद्रीकरण से जोड़कर देखता है। इस समय भाजपा के सामने भी चुनौती कम नहीं है उसे अपने समर्थकों का भरोसा बनाये रखने के साथ-साथ आलोचकों की चिंताओं को भी समझना होगा।

सबसे दिलचस्प बदलाव क्षेत्रीय दलों को लेकर आया है। कभी ये दल स्थानीय हितों के सबसे बड़े रक्षक माने जाते थे, लेकिन अब जनता इनके प्रति अधिक सतर्क और संदेहशील हो गई है। बंगाल और तमिलनाडु के परिणाम बताते हैं कि अगर ये दल पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं दिखाएंगे, तो जनता उन्हें बदलने में देर नहीं करेगी। तमिलनाडु में टीवीके की जीत ने जो संकेत दिया है वह केवल एक राज्य की घटना नहीं है, बल्कि एक नयी शुरुआत भी हो सकती है।

आने वाले समय में इन परिणामों का असर देश की राजनीति पर साफ दिखाई देगा। इससे राजनीति में अनिश्चितता बढ़ेगी। अब कोई भी दल यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसका जनाधार स्थायी है। राजनीतिक दलों को अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ानी होगी केवल घोषणाएं और वादे काफी नहीं होंगे अब जनता काम और परिणाम दोनो देखना चाहती है। नए दलों और नए नेतृत्व के लिये रास्ता खुलेगा। अगर एक नया दल तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में जीत सकता है, तो अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रयोग संभव हैं।

इन चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है भारत का मतदाता अब किसी के साथ स्थायी नहीं है, वह केवल अपने हितों के साथ स्थायी है। यह राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जो दल इस सच्चाई को समझेंगे और खुद को बदलेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। जो नहीं समझेंगे, उनके लिए यह जनादेश एक चेतावनी है। अब राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं रही, यह विश्वास की परीक्षा बन चुकी है, और इस परीक्षा में असफल होने वालों को दूसरा मौका मिलना तय नहीं है।

न वैराग्य और न भयंकर उपभोग, मध्यमार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ है पवित्र कुरान

गौतम चौधरी

इस्लामिक मान्यता के आधार पर पवित्र कुरान अल्लाह द्वारा अवतरित मार्गदर्शन की अंतिम पुस्तक है। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक दिशा प्रदान करता है, बल्कि जीवन का एक संपूर्ण विधान (जाब्ता-ए-हयात) भी है। कुरान का मूल संदेश जीवन के हर पहलू, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक, नैतिक या कानूनी हो, में संतुलन और मध्य मार्ग अपनाने पर जोर देता है। कुरान, बार-बार यह शिक्षा देता है कि अतिवाद और कट्टरता से बचकर ही एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना संभव है। यह ग्रंथ मनुष्य को सिखाता है कि वह अपने कार्यो और विचारों में स्थिरता लाए।

दरअसल, यह मैं नहीं कह रहा हूं। इस बात की चर्चा इस्लामिक विद्वान और स्तंभ लेखक मुजफ्फर हुसैन साहब ने कही है। विगत दिनों मुजफ्फर हुसैन साहब की एक किताब पढ़ने का मौका मिला। मुजफ्फर हुसैन द्वारा लिखी किताब, 'पवित्र कुरान और गौमांश' में उन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि पवित्र कुरान भी उसी तरह मांसाहार का निषेध करता है, जैसे हिन्दुओं के ग्रंथों में बताया गया है। किताब में कई चौकाने वाली बातें कही गयी है। बाकायदा पवित्र कुरान की आयतों का हवाला देते हुए कहा गया है कि गोहत्या पर महज एक जगह इब्राहिम-अले-इस्लाम की एक आयत है। जिसमें वे कहते हैं, 'विशेष परिस्थिति में काली गाय की कुर्बानी दी जा सकती है।' इस विषय पर जब मुफ्ती तुफैल खान साहब से चर्चा की तो उन्होंने पूरे कुरान को ही मध्यममार्गी बता दिया और कहा, 'कुरान केवल मुसलमानों के लिए नहीं, यह पूरी मानवता के लिए एक पवित्र ग्रंथ है।'

मुफ्ती तुफैल बताते हैं, ''कुरान की सूरह अन-नहल (आयत 90) में अल्लाह न्याय (अदल), श्रेष्ठता (एहसान) और रिश्तेदारों की मदद का स्पष्ट आदेश देता है। विद्वानों के अनुसार, यहाँ 'न्याय' का अर्थ केवल कानूनी बराबरी नहीं है, बल्कि विश्वास, कार्यो, चरित्र और भावनाओं में पूर्ण संतुलन बनाए रखना है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को न तो किसी चीज में अति (Excess) करनी चाहिए और न ही कमी (Deficiency) यहाँ तक कि शत्रुओं के साथ व्यवहार में भी न्याय का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान का आंतरिक और बाहरी जीवन एक समान होना चाहिए। वहीं 'एहसान' न्याय से एक कदम आगे की स्थिति है, जहाँ व्यक्ति न केवल अपने अनिवार्य कर्तव्य निभाता है, बल्कि दूसरों के प्रति क्षमाशील, कोमल और उदार भी होता है।''

इस्लाम के अन्य जानकारों का मानना है कि कुरान हमें तीन बड़ी बुराइयों से बचने की चेतावनी देता है, निर्लज्जता, बुराई और अत्याचार। ये तीनों मानवीय कमजोरियों, अनियंत्रित इच्छाओं, गुमराह सोच और बेलगाम क्रोध से जुड़ी हैं। एक व्यद्रि वास्तव में तभी परिष्कृत हो सकता है जब वह इन ताकतों को वश में करे और तर्क व नैतिक जागरूकता को अपना मार्गदर्शक बनाए। मध्यमार्ग का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि अल्लाह ने मुस्लिम समुदाय को 'उम्मते वस्त' यानी 'मध्य राष्ट्र' या संतुलित राष्ट्र कहा है। इसका अर्थ यह है कि इस समुदाय को जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करना है।

मौलाना बहिरुद्दीन खान कई मौकों पर यह दुहरा चुके हैं कि आस्था के मामले में, इस्लाम सिखाता है कि पैगंबरों के प्रति न तो अनादर हो और न ही उन्हें ईश्वर का दर्जा दिया जाए। इबादत के मामले में, इस्लाम न तो धर्म की पूरी उपेक्षा की अनुमति देता है और न ही दुनिया को छोड़कर वैराग्य अपनाने का समर्थन करता है। सच्चा धार्मिक मार्ग वह है जिसमें मनुष्य अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को निभाते हुए समाज में एक जिम्मेदार जीवन व्यतीत करे। सामाजिक स्तर पर, इस्लाम मानवाधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाता है। यह मानवीय गरिमा की रक्षा करता है और कठिन परिस्थितियों में भी निष्पक्षता की मांग करता है।

भारत में जन्में और बटवाड़े के बाद पाकिस्तान में जाकर बस गए डॉ. इसरार अहमद ने अपनी कई तकरीरों में कुरान को मानवीय मूल्यों का ग्रंथ बताया है। चुनांचे, आर्थिक जीवन में भी इस्लाम का दृष्टिकोण अत्यंत संतुलित है। यह न तो पूंजीवाद की तरह धन के असीमित संचय की छूट देता है और न ही साम्यवाद की तरह व्यक्तिगत स्वामित्व को पूरी तरह नकारता है। यह जकात और दान के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि धन का प्रवाह समाज के वंचित वर्गो तक बना रहे और वह केवल कुछ हाथों में केंद्रित न हो जाए।

अंत में इस्लामिक विचारकों और जानकारों की राय के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पवित्र कुरान मध्यमार्ग को जीवन के केंद्रीय सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता है। यह संतुलित दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत शांति सुनिश्चित करता है, बल्कि सामूहिक जीवन में भी सद्भाव, न्याय और लोक-कल्याण की नींव रखता है। यही वह मार्ग है जो मानवता को स्थिरता और गरिमा प्रदान करता है।

बुद्ध पूर्णिमा: करुणा का संदेश

श्री सी. पी. राधाकृष्णन
उपराष्ट्रपति

चित्रा पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, जब मंदिर उत्सव मनाए जा रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक घर में सुख-समृद्धि बढ़े। मुझे सभी भाईयों और बहनों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए प्रसन्नता हो रही है।

भारत ने विश्व को जो अनेक उपहार दिए हैं, उनमें बौद्ध धर्म सर्वोपरि है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश, आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशमान कर रहे हैं। भारत ने विश्व को आत्म- साक्षात्कार का महत्व सिखाया। बुद्ध शब्द का अर्थ ही है ''जाग्रत व्यक्ति''। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मानवता को आत्मज्ञान की राह दिखाने वाली इस महान आत्मा का जन्म और ज्ञान प्राप्ति, दोनों एक ही दिन हुए।

राजकुमार सिद्धार्थ का पालन-पोषण विलासिता में हुआ। 29 वर्ष की आयु में, उन्होंने अपना महल, पत्नी, पुत्र और समस्त सांसारिक धन-संपत्ति त्यागकर आध्यात्मिक सत्य की खोज में विचरण किया। छह वर्षों के गहन शोध के बाद, उन्होंने बोधगया के बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। चार आर्य सत्यों और नैतिक आचरण के मार्ग की प्राप्ति ने एक नए दर्शन का आरंभ किया, जिसने विश्व इतिहास में भारत के गौरव को नई ऊंचाई दी। वाराणसी के पास सारनाथ में उन्होंने पांच तपस्वियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। ''धर्मचक्र प्रवर्तन'' के नाम से प्रसिद्ध यह उपदेश बौद्ध धर्म की नींव बना और बौद्ध परंपरा की औपचारिक शुरुआत का यह प्रतीक था। समय के साथ, अनेक लोग उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। मगध के राजा बिम्बिसार ने राजगीर में वेणुवन (बांस उपवन) विहार दान किया। धनी अनाथपिंडिका ने पूरे जेतवन उपवन को स्वर्ण मुद्राओं से ढककर एक विहार(मठ) का निर्माण करवाया। ऐसे कार्य भारत में विद्यमान धर्मपरायणता में गहरी आस्था को दर्शाते हैं।

विहारों के माध्यम से चार आर्य सत्यों का प्रसार होता है: इच्छा दुख का मूल कारण है(इच्छा का त्याग करने से दुख पर विजय पाई जा सकती है, और अष्टांगिक मार्ग का पालन कर दुख से मुक्त जीवन जिया जा सकता है। बुद्ध ने सलाह दी: अतीत पर ध्यान न दें, वर्तमान में जिएं। सत्यनिष्ठा में महान शक्ति होती है। मन सभी कर्मों का मूल है, इसलिए सकारात्मक सोच विकसित करें। कठिन समय में भय से पीछे न हटें। जीवन की यात्रा अंततः व्यक्तिगत होती है, इसलिए इसे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाओ। शब्दों में घाव देने की शक्ति होती है, इसलिए मधुर वाणी बोलो। प्रेम और अहिंसा आवश्यक हैं। निरंतर सीखते रहो, कभी रुकें नहीं।

मणिमेकलई और कुंडलकेसी जैसे तमिल साहित्यिक ग्रंथों में बौद्ध दर्शन का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। हालांकि, अनेक प्राचीन ग्रंथ समय के साथ लुप्त हो गए, फिर भी उनका योगदान अमूल्य बना हुआ है।

'मदिरा जो मन को भ्रमित करती है, और जीव हिंसा
-बुद्धिमान, मोह से मुक्त होकर, इनका त्याग करते हैं, सुनो:
जन्म और मृत्यु, तथा मृत्यु के बाद पुनर्जन्म,
नींद और जागरण के समान हैं-यही सत्य है।
जो धर्मपूर्ण कर्म करते हैं, वे श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होते हैं,
और जो अधर्म करते हैं, वे गहन दुःख में गिरते हैं।'

इस सत्य को समझकर विवेकी जन अपने सभी बंधनों को तोड़ देते हैं।'

इस प्रकार महाकाव्य मणिमेकलै (आथिरै पिच्चैयिट्टा काथै: 84-90) बौद्ध धर्म के सार को स्पष्ट करता है। उन्होंने पांच नैतिक सिद्धांतों पर विशेष बल दिया- अहिंसा, चोरी न करना, व्यभिचार से दूर रहना, सत्य बोलना और नशीले पदार्थों से परहेज़ करना। धर्म से आगे बढ़कर उन्होंने सिखाया कि मन ही हर चीज़ की जड़ है।

सकारात्मक विचार और श्रेष्ठ कर्म ही व्यक्ति तथा समाज में संतुलन और शांति लाते हैं। अशांत मन को ज्ञान और स्पष्टता देने के कारण उन्हें 'एशिया का प्रकाश' कहा जाता है।

मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के शब्द याद आते हैं-'भगवान गौतम बुद्ध के जीवन का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया कि शांति की शुरुआत हमारे भीतर से होती है, उन्होंने यह एहसास कराया कि स्वयं पर विजय पाना ही सबसे बड़ी जीत है। आज जब दुनिया तनाव और संघर्ष के दौर से गुजर रही है, तब बुद्ध के उपदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।'

बुद्ध के उपदेशों की परिवर्तनकारी शक्ति इस बात से स्पष्ट होती है कि उन्होंने सम्राट अशोक जैसे युद्धप्रिय शासक को भी शांति और करुणा का समर्थक बना दिया। सम्राट अशोक ने शिलालेखों और स्तूपों के माध्यम से पूरे देश में बौद्ध सिद्धांतों का प्रचार किया। सांची और सारनाथ के स्तूप आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है।

अशोक ने भिक्षुओं और अपने परिवार के सहयोग से बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया। महावंश के अनुसार, उनके पुत्र महेंद्र बौद्ध उपदेशों को श्रीलंका ले गए। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं ने तमिलनाडु में भी इस धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां आज भी कई क्षेत्रों में बौद्ध परंपरा के चिन्ह मिलते हैं।

बौद्ध भिक्षु बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क चिकित्सा और शिक्षा प्रदान करते थे। वे त्रिपिटक जैसे पवित्र ग्रंथों की शिक्षा देते, जातक कथाएं सुनाते और लोगों को ध्यान साधना के माध्यम से जागरूकता का मार्ग दिखाते थे। दान, विशेषकर भूखों को भोजन कराना, एक मूल कर्तव्य माना जाता था। तमिल साहित्य में भी कहा गया है कि भूखे को भोजन देना मानो जीवन देने के समान है। हजारों वर्षों से इस भूमि पर अनेक आध्यात्मिक विचारधाराएं और दर्शन विकसित होते रहे हैं। चाहे बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, भारत ने हर मत और पंथ को एकात्म भावना से स्वीकार किया है। यह दर्शाता है कि सांस्कृतिक चेतना और साझा भावनाओं के स्तर पर यह राष्ट्र सदैव एक रहा है। बौद्ध धर्म ने आजीवन शिक्षा पर विशेष बल दिया और विशाल स्तर पर शिक्षण संस्थानों तथा पुस्तकालयों की स्थापना की। पांचवीं शताब्दी में ही नालंदा विश्वविद्यालय एक महान ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जहां लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1,500 आचार्य शिक्षा एवं अध्यापन में संलग्न थे।

नालंदा की तरह ही ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में भी एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालयों तथा अनेक साहित्यिक कृतियों ने विश्व के सामने भारत की बौद्धिक ऊंचाइयों को प्रदर्शित किया।

एशिया भर से विद्वान बौद्ध शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने भारत आते थे। चीनी भिक्षु फाह्यान की 15 वर्ष लंबी यात्रा विशेष रूप से बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए थी। इसी प्रकार चीनी विद्वान ह्वेनसांग ने 16 वर्षों तक भारत में रहकर नालंदा में अध्ययन किया, अनेक ग्रंथ संग्रहित किए औरफिर अपने देश लौटे।

अपने विस्तृत यात्रा-वृत्तांत में ह्वेनत्सांग ने उल्लेख किया है कि उन्होंने तमिलनाडु के कांचीपुरम का भी दौरा किया, जहां वे एक बौद्ध विश्वविद्यालय में ठहरे, अध्ययन किया और अनेक पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां तैयार कीं। कहा जाता है कि उन्होंने वहां विद्यार्थियों को विशेष व्याख्यान भी दिए।

कठोर तपस्या से अत्यंत दुर्बल हो चुके सिद्धार्थ के प्रति करुणा से प्रेरित होकर सुजाता ने उन्हें प्रेमपूर्वक खीर अर्पित की। इस करुणामयी सेवा ने उनका जीवन बचाया और उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने की शक्ति प्रदान की। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम सुजाता के इसी प्रेम और दया को स्मरण करते हुए खीर बनाकर अर्पित करते हैं।

''प्रेम ही आनंद का स्रोत है, प्रेम ही दुनिया की रोशनी है, और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है-''-बुद्ध की ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि पूरे विश्व में प्रेम और शांति का प्रसार हो।

नारंगी अर्थव्यवस्था: जनजातीय कला, हस्तशिल्प और आजीविका

- रंजना चोपड़ा -
जनजातीय कार्य मंत्रालय में सचिव

वर्शांग खैयर मणिपुर के उखरूल जिले के लॉन्गपी गांव के निवासी हैं, जो अपने और अपने परिवार की रोजी-रोटी गांव में उपलब्ध गारे और सर्पेंटीनाइट पत्थर से बर्तन बनाकर कमाते हैं। स्थानीय तांगखुल नागा जनजातियों के अनुसार, यह पारंपरिक शिल्प, देवी पंथोइबी की कृपा है और आज यह उनकी आय का मुख्य स्रोत है और इसने छोटे से गांव को वैश्विक मानचित्र पर ला दिया है। इसी तरह, नॉर्थी कुट्टन, जो तमिलनाडु के उद्हगमंडलम जिले के पागलकोड मंड गांव में रहते हैं, पारंपरिक कढ़ाई कला से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इस कढ़ाई कला का उपयोग नीलगिरी के हरे-भरे जंगलों में बसे टोडा जनजाति समूह द्वारा किया जाता है। जीआई टैग से युक्त यह शिल्प प्रकृति और सामुदायिक बंधन का जश्न मनाता है और इसे बहुत ही सुंदरता के साथ टेबल मैट, रनर, जैकेट आदि पर अंकित किया जाता है और समकालीन उपयोग में इसे लोकप्रियता भी मिली है। खैयर और कुट्टन दोनों अपने पारंपरिक जनजातीय कला रूपों के एक उन्नत रूप का अभ्यास करके सालाना लगभग 6-8 लाख रुपये कमाते हैं।

जनजातीय आजीविका लंबे समय से ज्ञान और पारंपरिक प्रथाओं पर आधारित रही है, जहां रचनात्मकता शिल्प, परंपरा, वस्त्र, संगीत, नृत्य, कथा-वाचन और भाषाओं में निहित है। ये केवल उत्पाद या सेवाएं नहीं हैं, बल्कि ज्ञान की जीवित विरासत हैं, जो पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। जनजातीय समुदायों के पास मौजूद रचनात्मक संपत्तियों का महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य है, जिसे यदि परंपरा के प्रति संवेदनशील रहते हुए सतत तरीके से उपयोग किया जाए, तो यह नारंगी अर्थव्यवस्था (ऑरेंज इकोनॉमी) को गति दे सकता है और इस इकोसिस्टम के तहत आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों का सृजन कर सकता है।

रचनात्मक अर्थव्यवस्था को दर्शाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली नारंगी अर्थव्यवस्था, यूएनसीटीएडी (संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन) के अनुमान के अनुसार 2 ट्रिलियन डॉलर से 2.25 ट्रिलियन डॉलर के बीच है, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 3.1% है। भारत में, जहां हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए ठोस डेटा मौजूद है, वहीं जनजातीय शिल्प और आजीविका के लिए डेटा की कमी है। हालांकि, रणनीतिक निहितार्थ स्पष्ट है:जनजातीय कला और शिल्प कुछ ऐसी ग्रामीण आजीविकाएं हैं, जो वैश्विक रचनात्मक वस्तुएं की मांग से सीधे जुड़ सकती हैं यदि प्रामाणिकता, लॉजिस्टिक्स और गुणवत्ता प्रणाली मौजूद हों। अनुमान है कि भारत की अनुसूचित जनजाति की आबादी 104 मिलियन है और कुल आबादी में इसकी हिस्सेदारी लगभग 8.6% है। लगभग 700 अलग-अलग जनजातीय समुदाय विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों में निवास करते हैं: जंगल, पहाड़, मैदान और सीमा क्षेत्र। इस विविधता का प्रत्यक्ष आर्थिक संबंध है। यह पारिस्थितिकी के अनुसार शिल्प विशेषज्ञता को प्रतिबिंबित करता है, जैसे जंगल वाले क्षेत्रों में बांस और छड़ी, खनिज क्षेत्रों में धातु और मिट्टी, और बुनाई गलियारों में वस्त्र परंपराएं। इसके परिणामस्वरूप, भारत के जनजातीय क्षेत्र, एकल जनजातीय शिल्प क्षेत्र के बजाय 'विविध अर्थव्यवस्थाओं' से युक्त हैं। इसलिए, नीति निर्माण क्षेत्रीय रूप से भिन्न होना चाहिए और 'सभी के लिए उपयुक्त एक ही शिल्प योजना' नहीं होनी चाहिए। नीतियों को कच्चे माल की सीमाओं, डिज़ाइन और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों और बाजार संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए।

वर्तमान में, जनजातीय कला/हस्तशिल्प आजीविका इकोसिस्टम, कई मंत्रालयों और संस्थानों के कार्यादेशों से बना है, जो विभिन्न स्तरों पर एक-जैसे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय इस इकोसिस्टम का मुख्य स्तंभ है और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक अवसंरचना में सुधार करता है और ट्राइफेड (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड) के माध्यम से बाजार-जुड़ाव की सुविधा देता है। ट्राइफेड एक प्रमुख बाजार संचालक के रूप में कार्य करता है। ट्राइफेड वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) का समर्थन करता है, जो खरीद और मूल्य संवर्धन के लिए जमीनी स्तर की इकाइयां हैं। ट्राइफेड, ट्राइब्स इंडिया आउटलेट और आदि महोत्सव/हाट्स के माध्यम से खुदरा विपणन करता है ताकि उत्पादकों को खरीदारों और संस्थागत भागीदारों से जोड़ा जा सके। वस्त्र मंत्रालय राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के माध्यम से हस्तशिल्प को बढ़ावा देता है और समग्र हथकरघा/हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजनाओं (सीएचसीडीएस) के माध्यम से क्लस्टर अवसंरचना को प्रोत्साहन देता है और कारीगरों के डेटाबेस को अद्यतन करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) पारंपरिक उद्योग पुनरुत्थान निधि योजना (स्फूर्ति) के माध्यम से क्लस्टर पुनरुत्थान और बिक्री-योग्यता का समर्थन करता है, स्पष्ट रूप से आपूर्ति-संचालित मॉडल के बदले बाज़ार-संचालित मॉडल का उपयोग करता है और ई-कॉमर्स को एक माध्यम के रूप में महत्व देता है। अनुभव से पता चलता है कि ग्रामीण आजीविका मूल्य-श्रृंखला चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ये कमजोर हैं, कारीगर सीधे बाजार से जुड़े नहीं होते हैं और मध्यस्थों पर अधिक निर्भर रहते हैं। ये कारक लाभ कम कर देते हैं तथा खराब भंडारण और एकत्रीकरण की वजह से अर्थव्यवस्था के विस्तार को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि हम विश्लेषण को कारीगर परिवारों के स्तर तक और गहराई से देखें, तो जो पैटर्न दिखाई देता है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। कारीगर शिल्प कार्य को सहायक या अंशकालिक रोजगार के रूप में देखते हैं, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में, जहां कृषि मौसम-आधारित है या परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इस परिस्थिति में, खराब ऋण पात्रता और उद्यम विकास, बाजार से जुड़ाव की कमी और व्यापारियों पर निर्भरता से आय प्रवाह अनियमित हो जाता है। हालांकि, शिल्प कम पूंजी में घर पर उत्पादित किए जा सकते हैं, जिनमें उच्च लाभ की संभावना भी हो सकती है। शिल्प हस्तक्षेप अक्सर महिलाओं के रोजगार, आय और सौदेबाजी की शक्ति से जुड़े कार्यक्रम होते हैं। मोटे अनुमान बताते हैं कि 7 मिलियन से अधिक कारीगरों में महिलाओं की हिस्सेदारी 56% से 70% से अधिक हैं और हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों में 72.29% महिलाएं हैं। कौशल हस्तांतरण अनौपचारिक होता है और आमतौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता है। जनजातीय कला रूपों के लिए, जहां तकनीक और आख्यान में सांस्कृतिक अर्थ निहित होता है, वहां हस्तांतरण दोनों तरह का होता है- आर्थिक (कौशल) और सांस्कृतिक (प्रामाणिकता)। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत तीन मौजूदा मॉडल मजबूत जुड़ाव के उपाय प्रदान करते हैं: वीडीवीके जैसी उत्पादनकर्ता समितियां, जो साझा अवसंरचना और संग्रहण प्रदान करती हैं (ट्राइब्स इंडिया स्टोर जो खरीदार से जोड़ने में मदद करते हैं और राज्य स्तर पर क्लस्टर विकास और कौशल उन्नयन के लिए सहकारी संस्थाएं। उदाहरण के लिए, ओडिशा में 150 वीडीवीके कार्यरत हैं जिनकी कुल बिक्री 2,459.91 लाख रूपये है और जिसमें लगभग 40,000 जनजातीय उत्पादकों को एकीकृत किया गया है। जनजातीय विकास सहकारी निगम एक उच्च स्तरीय सहकारी संस्था है, जो जनजातीय उत्पादकों द्वारा तैयार किये गये वन और गैर-वन आधारित वस्तुओं के विपणन और ब्रांडिंग का कार्य करती है। यह भारत के लिए एक मुख्य रणनीतिक सिफारिश को रेखांकित करता है: नारंगी अर्थव्यवस्था में जनजातीय कला/हस्तशिल्प को बेहतर क्षेत्रीय लेखांकन, लागू करने योग्य प्रामाणिकता/नैतिक व्यापार संरचना, और उत्पादक-संचालित वितरण की आवश्यकता है, जो मध्यस्थों के प्रभाव को कम करता हो। लघु-अवधि के लिए भारत ट्राइब्स फेस्ट जैसे त्योहारों को खरीद संभावना तथा उत्पाद कैटलॉग के मानकीकरण और डिजिटलीकरण के रूप में देखा जाना चाहिए एवं राष्ट्रीय एसटी वित्त विकास निगम और पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के माध्यम से ऋण समर्थन को खरीदार आदेशों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। हालांकि, दीर्घ-अवधि के लिए सरकार को एक जनजातीय रचनात्मक अर्थव्यवस्था उपग्रह विवरण बनाने, निर्यात स्तर की अनुपालन और ब्रांड संरचना स्थापित करने और जनजातीय कला के लिए भारत-उपयुक्त नैतिक व्यापार संहिता तैयार करने पर विचार करना होगा। इन उपायों के माध्यम से, जनजातीय नारंगी अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों से उभरकर विकसित भारत @2047 की यात्रा में शामिल हो जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में एसजेवीएन की जलविद्युत परियोजनाओं की समीक्षा

शिमला/शैल। भारत सरकार के सचिव (विद्युत) पंकज अग्रवाल ने अपर सचिव (हाइड्रो एवं ईसी एंड ईटी) दिवाकर नाथ मिश्रा तथा सदस्य (हाइड्रो), सीईए मिलिंद गणेश गोखले के साथ हिमाचल प्रदेश में एसजेवीएन की जलविद्युत परियोजनाओं का दौरा किया। दौरे के दौरान, उन्होंने 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन, 210 मेगावाट लूहरी-1 जलविद्युत परियोजना, 412 मेगावाट रामपुर जलविद्युत स्टेशन तथा 382 मेगावाट सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना में परिचालन और निर्माण कार्यों की समीक्षा की।

सभी गणमान्य अतिथियों का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन भूपेंद्र गुप्ता, निदेशक (कार्मिक) अजय कुमार शर्मा, निदेशक (वित्त) पार्थजीत डे, सीएमडी के ओएसडी राजेश कुमार चंदेल तथा परियोजना प्रमुखों ने स्वागत किया।

1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन में पंकज अग्रवाल एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने विद्युत गृह का दौरा किया और उन्हें रखरखाव के सर्वोत्तम तरीकों, प्रमुख वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर तथा विद्युत उत्पादन में पावर स्टेशन द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों से अवगत कराया गया। 412 मेगावाट रामपुर जलविद्युत स्टेशन में उन्होने पर्यावरणीय सततता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पौधारोपण भी किया।

पंकज अग्रवाल ने 210 मेगावाट लूहरी-1 जलविद्युत परियोजना में

निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बांध के कार्य, विद्युत गृह और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल इंस्टॉलेशन सहित परियोजना के प्रमुख घटकों की स्थिति का जायज़ा लिया और साथ ही साइट से जुड़ी चुनौतियों का भी संज्ञान लिया। निर्धारित समय-सीमा के पालन के महत्व पर बल देते हुए, उन्होंने परियोजना टीम को गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया ।

382 मेगावाट सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना में पंकज अग्रवाल ने सतलुज नदी पर खैरा में एक डबल-लेन स्टील ट्रस ब्रिज का उद्घाटन किया। परियोजना के निर्माण कार्यों को सुगम बनाने के साथ-साथ, यह नवनिर्मित पुल मंडी और शिमला जिलों की दूरवर्ती परियोजना प्रभावित पंचायतों तक संपर्क को भी काफी बेहतर बनाएगा। इससे स्थानीय समुदायों के सामाजिक -आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। उन्होंने परियोजना प्रगति की समीक्षा करने के लिए बांध स्थल, मशीन हॉल क्षेत्र और टेल रेस टनल के घटकों का भी दौरा किया।

ऊर्जा सचिव ने ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों को हासिल करने और निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में एसजेवीएन टीम के समर्पण की सराहना की। इस दौरे ने भारत सरकार की जलविद्युत क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा संरचना के विकास को तीव्र गति देने की प्रतिबद्धता को दर्शाया है।

12वीं परीक्षा परिणामों पर शिक्षा मंत्री की बधाई

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कुल 81,417 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 74,637 विद्यार्थी सफल रहे और कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 92.02 प्रतिशत दर्ज किया गया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह परिणाम पिछले वर्षो की तुलना में बेहतर है और राज्य सरकार तथा शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर सुधारों के सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि मेरिट सूची में सर्वाधिक विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों से हैं, जो सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में हुए सुधार का प्रमाण है।

उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग को दिया। विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत की है।

रोहित ठाकुर ने छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की विशेष सराहना करते हुए बताया कि इस वर्ष भी छात्राओं ने छात्रों से बेहतर परिणाम हासिल किए हैं। 40,281 छात्राओं में से 37,749 सफल रहीं, जबकि 40,828 छात्रों में से 36,888 छात्र उत्तीर्ण हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियों का यह प्रदर्शन गर्व का विषय है और उनकी प्रतिभा व दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें निरंतर मेहनत करने, उच्च लक्ष्य निर्धारित करने और समाज व राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

शिक्षा मंत्री ने सड़क हादसे में घायल शिक्षकों का जाना कुशल-क्षेम

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आईजीएमसी पहुंचकर आनी में शनिवार शाम हुई सड़क दुर्घटना में घायल शिक्षकों का हालचाल जाना। उन्होंने अस्पताल में भर्ती शिक्षकों रीना कुमारी और तारा देवी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा चिकित्सकों से उपचार संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

शिक्षा मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने इस दुर्घटना में चार शिक्षकों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं।

रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने घायल शिक्षकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।

सीपीआरआई में आलू मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ करने पर जोर

शिमला/शैल। डॉ एम. एल. जाट, सचिव (DARE) एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1 मई 2026 को केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला का दौरा कर आलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। उनके साथ डॉ सुधाकर पांडे भी उपस्थित रहे।

दौरे के दौरान डॉ. जाट ने संस्थान संग्रहालय और जीनोम एडिटिंग उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एरोपोनिक्स सुविधा, पादप संरक्षण प्रयोगशालाएं, फसलोत्तर एवं बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं, आलू जर्मप्लाज्म भंडार और जीनोम एडिटिंग लैब सहित विभिन्न अनुसंधान सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ ब्रजेश सिंह ने संस्थान की अनुसंधान, बीज उत्पादन और विस्तार गतिविधियों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

संस्थान में आयोजित संवाद सत्र में डॉ. जाट ने अनुसंधान नैतिकता, सुदृढ़ डेटा प्रबंधन, प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी नवाचारों के प्रभावी प्रसार पर बल दिया। उन्होंने पोषक तत्वों से भरपूर किस्मों के विकास की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए छात्रों को कृषि क्षेत्र में नवाचार के अवसरों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही, उन्होंने रिसर्च डेटा प्रबंधन नीति, संचार रणनीति, जेंडर समावेशन और निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र (MELIA) की जानकारी भी साझा की।

दोपहर सत्र में आलू मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना विषय पर हितधारक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आईसीएआर संस्थानों, बीज कंपनियों, प्रसंस्करण उद्योगों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। चर्चा के प्रमुख बिंदुओं में बीज प्रणाली को पारदर्शी बनाना, स्वच्छ रोपण सामग्री की उपलब्धता, निर्यात संभावनाएं, रियल-टाइम बीज जानकारी और किसानों की गुणवत्तापूर्ण बीज तक पहुंच शामिल रही।

सम्मेलन से प्राप्त सुझावों के आधार पर बीज से लेकर प्रसंस्करण और बाजार तक आलू मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने की व्यापक रूपरेखा तैयार की गई। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन गुणवत्ता सुधारने और कृषि क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

फोर्टिस मोहाली में एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट से बढ़ी मरीजों की उम्मीदें

शिमला/शैल। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में कैंसर उपचार के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग से मरीजों को बेहतर और सुरक्षित इलाज मिल रहा है। अस्पताल के ब्रेस्ट एवं एंडोक्राइन सर्जरी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग ने मिलकर हाल ही में एक युवा महिला मरीज का सफल इलाज किया, जिससे उन्नत

चिकित्सा सुविधाओं की प्रभावशीलता सामने आई है।

अस्पताल के विशेषज्ञ डॉ. नरेंद्र भल्ला (डायरेक्टर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी) और डॉ. नवल बंसल (सीनियर कंसल्टेंट, ब्रेस्ट एवं एंडोक्राइन सर्जरी) की टीम ने 28 वर्षीय महिला का इलाज किया, जिसे बाएं ब्रेस्ट में शुरुआती स्टेज का कैंसर था। मरीज में ब्रेस्ट के आकार में बदलाव, निप्पल का अंदर जाना और त्वचा में लालिमा जैसे लक्षण दिखाई दिए थे।

जांच के बाद डॉक्टरों ने पारंपरिक पद्धति के बजाये ब्रेस्ट बचाने वाली सर्जरी (Breast Conserving Surgery) का विकल्प चुना। इसके साथ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी भी की गई, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैंसर अन्य हिस्सों में नहीं फैला है। सर्जरी के दौरान ही टिशू की जांच में पाया गया कि ट्यूमर पूरी तरह हट चुका है और लिम्फ नोड्स सुरक्षित हैं। मरीज को अगले ही दिन डिस्चार्ज कर दिया गया।

सर्जरी के बाद आधुनिक एलेक्टा वर्सा एचडी मशीन के माध्यम से सरफेस गाइडेड रेडिएशन थेरेपी (SGRT) दी गई। इस तकनीक से केवल प्रभावित हिस्से पर सटीक रेडिएशन दिया जाता है, जिससे आसपास के स्वस्थ ऊतकों को नुकसान कम होता है और साइड इफेक्ट्स भी घटते हैं।

डॉ. भल्ला के अनुसार, नई रेडिएशन तकनीक से इलाज अधिक सटीक और सुरक्षित हुआ है, जबकि डॉ. बंसल ने बताया कि सही सर्जरी और सटीक रेडिएशन के संयोजन से कैंसर के दोबारा होने का खतरा भी कम हो जाता है।

सूचना एवं जन संपर्क विभाग में सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित

शिमला/शैल। सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय में अधीक्षक ग्रेड-1 बलवीर सिंह तथा कंप्यूटर ऑपरेटर हरीश चंद्र शर्मा के सेवानिवृत्ति उपलक्ष्य में एक गरिमामय विदाई समारोह आयोजित किया गया।

बलवीर सिंह ने 19 जनवरी, 1987 को विभाग में क्लर्क के पद पर अपनी सेवाएं प्रारंभ की थीं। लगभग 39 वर्षो के अपने लंबे कार्यकाल में उन्होंने ईमानदारी, प्रतिबद्धता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हुए विभाग में एक विशिष्ट पहचान बनाई। वे अपने अनुशासन, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी के लिए सदैव सराहे गए। विभाग की विभिन्न शाखाओं को सुदृढ़ बनाने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनका कार्य व्यवहार, पेशेवर दक्षता और जिम्मेदारियों को सहजता से निभाने की क्षमता उन्हें विभाग का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान सदस्य बनाती रही।

हरीश चंद्र शर्मा ने 13 अप्रैल, 2006 को कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में अपनी सेवाएं आरंभ की थीं। लगभग 20 वर्षो की सेवा अवधि में उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कुशलता के साथ किया। उन्होंने प्रत्येक कार्य को उत्साह, तत्परता और धैर्य के साथ सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिससे विभागीय कार्यो में निरंतर दक्षता बनी रही।

इस अवसर पर संयुक्त निदेशक अजय पाराशर ने दोनों अधिकारियों के योगदान की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ, खुशहाल और सुखद जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण भाव से दी गई सेवाएं सदैव अन्य कर्मचारियों के लिए अनुकरणीय होती हैं।

समारोह में उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी दोनों सेवानिवृत्त अधिकारियों को शांतिपूर्ण, सुखद एवं आनंदमय जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।

भाजपा की जीत नेतृत्व पर जनता के भरोसे का परिणाम:विपिन परमार

शिमला/शैल। तीन राज्यों में भाजपा की चुनावी जीत के बाद शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय दीप कमल, चक्कर में कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ जश्न मनाया। इस दौरान पार्टी

पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन परमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस जीत को ऐतिहासिक बताया और इसे केंद्र सरकार की नीतियों तथा नेतृत्व पर जनता के भरोसे का परिणाम बताया।

परमार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह परिणाम दर्शाता है कि देश की जनता आज भी मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और भाजपा की विकासोन्मुखी नीतियों को स्वीकार कर रही है। उनके अनुसार यह जीत केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और पार्टी की विचारधारा की जीत है।

पश्चिम बंगाल की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए परमार ने कहा कि राज्य में लगभग 15 वर्षों के बाद सत्ता परिवर्तन के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में व्यापक असंतोष है और इस बार मतदाताओं ने बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने इसे एक संभावित ऐतिहासिक परिवर्तन बताते हुए कहा कि भाजपा पहली बार राज्य में सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

विपिन परमार ने भाजपा की जीत के पीछे कई कारण गिनाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बनी सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता में नाराजगी रही है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कथित गुंडागर्दी के खिलाफ भी लोगों में आक्रोश रहा, जिसका असर चुनाव परिणामों में दिखाई दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने इस बार अपनी रणनीति को बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू किया और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया, जिससे पार्टी को व्यापक जनसमर्थन मिला।

अपने संबोधन के अंत में परमार ने कहा कि यह जीत आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा तय करने वाली साबित होगी। उन्होंने कहा कि जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति के बजाये विकास, पारदर्शिता और सुशासन को प्राथमिकता देती है।

नगर निकाय चुनावों में जनता देगी कांग्रेस को जवाब: डॉ. बिंदल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनावों के नामांकन के अंतिम दिन सियासी माहौल गरमा गया

है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेशभर में सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव मैदान में उतर चुकी है और जनता इस बार कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देने के लिए तैयार है।

उन्होंने बताया कि धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों सहित 22 नगर पालिकाओं और 25 नगर पंचायतों में भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। नगर निगमों में पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अन्य जगहों पर भारतीय निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत समर्थित उम्मीदवारों के माध्यम से चुनाव होगा।

कांग्रेस सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुखू के नेतृत्व वाली सरकार ने तीन साल में हर वर्ग को निराश किया है। चुनाव से पहले दी गई गारंटियां अब झूठ साबित हो चुकी हैं और जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, उन्होंने कहा।

महिलाओं से किए वादों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1500 प्रतिमाह देने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि 1 लाख सरकारी नौकरियों और 5 लाख रोजगार के दावे भी हकीकत से दूर हैं, जिससे युवा वर्ग में निराशा बढ़ी है।

सिरमौर जिला का हवाला देते हुए बिंदल ने कहा कि विकास कार्य ठप पड़े हैं और केवल केंद्र सरकार की परियोजनाएं ही आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य संस्थान बंद हुए हैं, जिससे आम जनता पर असर पड़ा है।

उन्होंने कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक हालात पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में विकास की रफ्तार थम गई है और हर वर्ग सरकार से नाराज है।

डॉ. राजीव बिंदल ने भरोसा जताया कि नगर निकाय चुनावों में जनता कांग्रेस को कड़ा जवाब देगी और भाजपा को व्यापक समर्थन मिलेगा।

बेटी है अनमोल योजना के तहत छात्राओं को तीन साल से नहीं मिली सहायता: बलदेव तोमर

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने 'बेटी है

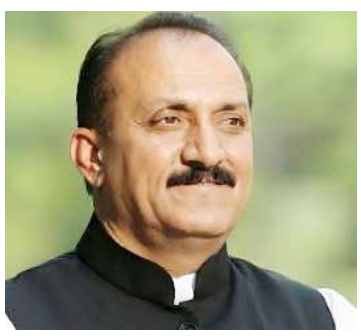

अनमोल' योजना के तहत पिछले तीन वर्षों से छात्राओं को आर्थिक सहायता न मिलने के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि गरीब परिवारों की बेटियों के भविष्य के साथ अन्याय करार दिया।

तोमर ने कहा कि यह योजना बीपीएल परिवारों की बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह पूरी तरह ठप हो गई है। तीन-तीन साल तक छात्रवृत्ति न मिलना इस बात का प्रमाण है कि सरकार को बेटियों की शिक्षा की कोई चिंता नहीं है, उन्होंने कहा।

उन्होंने दावा किया कि प्रदेशभर में हजारों छात्राएं इस योजना की लाभार्थी हैं, जिनमें से बड़ी संख्या को लंबे समय से कोई सहायता नहीं मिली। उनके अनुसार, सीमित संसाधनों वाले परिवारों के लिए यह स्थिति बेहद कठिन है और इससे बेटियों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है।

बलदेव तोमर ने आरोप लगाया कि सरकार योजनाओं के नाम बदलकर और घोषणाएं कर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर लाभ नहीं पहुंच रहा। उन्होंने कहा कि 'इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना' जैसे नए नामों के बावजूद लाभार्थियों को समय पर सहायता नहीं मिल रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय स्तर पर बजट की मांग भेजे जाने के बावजूद स्वीकृति नहीं मिलना गंभीर चिंता का विषय है और यह सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ छात्रवृत्ति रोक दी गई है यह सरकार का दोहरा चरित्र है, उन्होंने कहा।

तोमर ने कहा कि योजना के तहत मिलने वाली 500 से 5000 रुपये तक की राशि भले छोटी लगे, लेकिन गरीब परिवारों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने सरकार से लंबित राशि जल्द जारी करने और योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि समाधान न होने पर भाजपा इस मुद्दे को जनआंदोलन का रूप देगी।

नर्सिंग छात्राओं में टीबी संक्रमण के मामलों को लेकर सरकार पर बरसे जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रामपुर खनेरी स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल नर्सिंग संस्थान में नर्सिंग छात्राओं के टीबी संक्रमित होने के मामले को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 90 में से 19 छात्राओं का टीबी से संक्रमित होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और सरकार की बड़ी नाकामी को दर्शाता है।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि एक ही परिसर में इतनी बड़ी संख्या में संक्रमण फैलने के बावजूद सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देशभर में टीबी उन्मूलन के लिए व्यापक योजनाएं चला रही है और राज्यों को पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसके बावजूद प्रदेश में इस तरह की स्थिति चिंताजनक है।

उन्होंने यह भी कहा कि परिजनों द्वारा लिखे गए पत्र से स्पष्ट होता है कि कई छात्राएं एमडीआर-टीबी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, जो समय पर उचित उपचार न मिलने का संकेत है। साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि कुछ मामलों में छात्राओं को इलाज के बजाय झाड़फूंक की सलाह दिए जाने के आरोप सामने आए हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मांग की कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और संक्रमण को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं।

पंचायती राज चुनावों से पहले भाजपा सख्त अनुशासनहीनता पर होगी तुरंत कारवाई

शिमला/शैल। डॉ. राजीव बिंदल ने आगामी पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों को लेकर पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी लाइन से हटकर कार्य करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ तत्काल और सख्त कारवाई की जाएगी।

शिमला में जारी ब्यान में डॉ. बिंदल ने बताया कि चुनावों के दौरान अनुशासन बनाए रखने और गतिविधियों की निगरानी के लिए भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने एक विशेष अनुशासन समिति का गठन किया है। यह समिति पूरे प्रदेश में चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेगी और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की स्थिति में कारवाई की अनुशंसा करेगी।

उन्होंने बताया कि समिति में वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें डॉ. सिकंदर कुमार, विपिन सिंह परमार, बिहारी लाल शर्मा, इंदु गोस्वामी और बलबीर वर्मा शामिल हैं।

डॉ. बिंदल ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित और सिद्धांत आधारित संगठन है, जहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि टिकट वितरण, प्रचार-प्रसार और संगठनात्मक निर्णयों के दौरान किसी भी प्रकार की बगावत या अनुशासनहीनता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन की मर्यादा बनाए रखने और सामूहिक नेतृत्व की भावना से कार्य करने का आहवान किया। डॉ. बिंदल ने कहा कि भाजपा इन चुनावों में पूरी एकजुटता और मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी तथा अनुशासन ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है।

पेंशन भुगतान में देरी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जयराम ठाकुर ने उठाये सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी पेंशन में देरी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि महीने की 28 तारीख बीतने को है, लेकिन हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को अब तक पेंशन नहीं मिली है, जिससे वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पेंशन भुगतान के लिए 15 तारीख निर्धारित होने के बावजूद बार-बार देरी हो रही है और पेंशनरों को केवल आश्वासन मिल रहे हैं। शादी का सीजन चल रहा है और लोग अपनी पेंशन पर निर्भर हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तीन साल से अधिक समय से मेडिकल बिल लंबित हैं, जिससे कई लोग कर्ज लेकर इलाज कराने को मजबूर हैं।

सरकार के स्वास्थ्य संबंधी फैसलों पर सवाल उठाते हुए जय राम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर तुगलकी फैसले लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कमला नेहरू अस्पताल के गायनी विभाग को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करने से महिलाओं को भारी परेशानी हो रही है और पर्याप्त तैयारियां भी नहीं की गई।

रोबोटिक सर्जरी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मशीन लाने के बावजूद अब तक एक भी सर्जरी नहीं हुई है, जबकि मरीजों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ डाला जा रहा है। ठाकुर ने कहा कि दवाइयों और जांच की सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे लोगों को निजी संस्थानों का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इन मुद्दों पर जवाब देने और तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की।

नगर निगम मंडी के 15 वार्डों के नामांकन पत्रों की जांच संपन्न सभी नामांकन सही पाए गए

शिमला/शैल। नगर निगम मंडी के 15 वार्डों के पार्षद चुनावों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई। जांच के दौरान सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए, जिससे अब चुनाव मैदान में कुल 53 प्रत्याशी रह गए हैं। 29, 30 अप्रैल और 2 मई को कुल 59 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, जिनमें छह प्रत्याशियों ने दो-दो सेट जमा किए थे। अतिरिक्त सेट नियमों के तहत निरस्त किए गए। वार्ड 1 से 13 तक की जांच डीआरडीए हॉल में हुई, जबकि वार्ड 14 और 15 के नामांकन एसडीएम बल्ह कार्यालय में जांचे गए। प्रत्याशी 6 मई तक नाम वापस ले सकेंगे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

बड़े नेताओं की सक्रियता से भाजपा ने बढ़ाया चुनावी तापमान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भाजपा इस बार पूरी तैयारी और संगठित रणनीति के साथ मैदान में उतरती दिखाई दे रही है। टिकट वितरण से लेकर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने तक भाजपा ने जिस तेजी और अनुशासन का प्रदर्शन किया है, उसने चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। 64 में से 63 वार्डो में प्रत्याशियों की घोषणा कर भाजपा ने साफ संकेत दिया है कि वह इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही। केवल सोलन नगर निगम के वार्ड नंबर 7 का उम्मीदवार घोषित होना बाकी है। इसके विपरीत कांग्रेस अभी कई जगह उम्मीदवार चयन और स्थानीय असंतोष जैसी चुनौतियों से जूझती नजर आ रही है।

भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका बहुस्तरीय चुनावी प्रबंधन मॉडल माना जा रहा है। पार्टी ने चुनाव संचालन को प्रदेश, जिला और वार्ड स्तर पर विभाजित कर जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। प्रदेश स्तर पर रणनीतिक टीम चुनावी नैरेटिव और प्रचार अभियान संभाल रही है, जबकि जिला स्तर पर स्थानीय समीकरणों के अनुसार रणनीति को लागू किया जा रहा है। वहीं वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम बूथ प्रबंधन और मतदाताओं तक सीधी पहुंच बनाने में जुटी है। भाजपा अब हर वार्ड में प्रभारी नियुक्त करने जा रही है, जिससे चुनावी प्रबंधन को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

हालांकि सोलन में टिकट वितरण के बाद कुछ असंतोष सामने आया, लेकिन भाजपा ने त्वरित डैमेज कंट्रोल कर स्थिति संभालने की कोशिश की। वरिष्ठ नेताओं को सक्रिय कर नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का प्रयास किया गया। यह भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें पार्टी चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के अंदरूनी नुकसान को तुरंत नियंत्रित करना चाहती है।

भाजपा ने इस चुनाव में अपने बड़े नेताओं को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, राजीव भारद्वाज, इंदु गोस्वामी और डॉ. सिकंदर कुमार लगातार चुनावी क्षेत्रों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। बड़े नेताओं की सक्रियता से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है।

धर्मशाला में भाजपा ने नामांकन प्रक्रिया को भी शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने सभी पार्षद उम्मीदवारों के साथ सामूहिक रूप से नामांकन दाखिल कर एकजुटता का संदेश दिया। राजनीतिक रूप से इसे कांग्रेस के मुकाबले भाजपा की मजबूत स्थिति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। मंडी नगर निगम में भी भाजपा खुद को मजबूत स्थिति में मान रही है, क्योंकि यहां लंबे समय से पार्टी का संगठनात्मक आधार मजबूत रहा है।

हालांकि चुनावी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। स्थानीय मुद्दे, बगावती उम्मीदवार और मतदान प्रतिशत जैसे कई कारक अंतिम परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में तेजी लाने की तैयारी में है और स्थानीय असंतोष को भाजपा के खिलाफ मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकती है। इसके बावजूद शुरुआती चरण में भाजपा की संगठित तैयारी, समय पर टिकट वितरण और मजबूत चुनावी प्रबंधन उसे बढ़त दिलाते दिखाई दे रहे हैं।

नगर निगम चुनावों को केवल स्थानीय निकाय चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इन्हें आने वाले बड़े राजनीतिक मुकाबलों से पहले दोनों प्रमुख दलों की संगठनात्मक ताकत की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में भाजपा का यह आक्रामक और योजनाबद्ध अभियान आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति पर भी असर डाल सकता है।

महिलाओं से किए वादे निभाने में विफल रही सरकार:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। जयराम ठाकुर ने इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना को लेकर राज्य सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार को बने साढ़े तीन साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन चुनावों के दौरान महिलाओं से किए गए बड़े वादे आज भी अधूरे पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह गई है और लाखों महिलाएं आज भी अपने आवेदन पत्रों और वादों का हिसाब मांग रही हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की 18 से 59 वर्ष की महिलाओं से 1500 रुपये प्रतिमाह देने के नाम पर बड़े पैमाने पर फॉर्म भरवाए थे। ये फॉर्म कांग्रेस कार्यालयों और विभिन्न शिविरों के माध्यम से जमा करवाए गए। बाद में लोकसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की, लेकिन इसके साथ कई पात्रता शर्तें जोड़ दी गईं। इसके बावजूद प्रदेशभर में करीब 10 लाख महिलाओं ने आवेदन किए।

उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज बनवाने में अपना पैसा खर्च किया, कई बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए और लंबी प्रक्रियाओं से गुजरीं। लेकिन दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि इन फॉर्म्स की स्थिति क्या है। जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि आखिर वे आवेदन कहां हैं और कब तक महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार अब चयनित क्षेत्रों तक ही योजना को सीमित कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ने मनाली और सुलह विधानसभा क्षेत्रों में मंच से घोषणा की थी कि अप्रैल महीने से महिलाओं के खातों में 1500 रुपये आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अप्रैल बीतने के बाद भी किसी महिला को भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि योजना वास्तव में लागू करनी थी तो इसे पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए था।

जयराम ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 42 महीने पूरे हो चुके हैं और यदि चुनावी वादे के अनुसार हर महिला को राशि दी जाती तो अब तक 42 किश्तें महिलाओं के खातों में पहुंच जानी चाहिए थीं। उन्होंने कहा कि यह वादा किसी छोटे नेता ने नहीं बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों ने किया था। इसलिए अब सरकार को महिलाओं के सामने जवाब देना चाहिए।

उन्होंने सरकार पर महिलाओं से जुड़ी कई कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का आरोप भी लगाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि शगुन योजना, कन्यादान योजना और बेटी है अनमोल जैसी योजनाएं या तो बंद कर दी गई हैं या प्रभावहीन बना दी गई हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं के इलाज से जुड़ी व्यवस्थाओं को कमजोर किया गया और महिला स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महिलाओं ने कांग्रेस पर भरोसा कर वोट दिया था, लेकिन अब वही महिलाएं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर आगामी विधानसभा चुनावों तक नारी शक्ति इस मुद्दे पर अपना जवाब देगी।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की महिलाएं अपने सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और वे अपने साथ किए गए वादाखिलाफी को लंबे समय तक नहीं भूलेंगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि योजना की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए और महिलाओं से किए गए वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।